



डाकघर अधिनियम, 2023: औपनिवेशिक वधिका प्रतस्थापन

यह एडिटोरियल 22/01/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["Post Office Act, its unbridled powers of interception"](#) लेख पर आधारित है। इसमें संसद द्वारा हाल ही में पारित किये गए डाकघर अधिनियम 2023 पर विचार किया गया है जो औपनिवेशिक युग के भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतस्थापित करेगा। लेख में नए अधिनियम में लाये गए गहन परिवर्तनों और इसमें नहिति खामियों, विशेष रूप से केंद्र सरकार को सौंपी गई व्यापक शक्तियों के संबंध में, पर विचार किया गया है।

प्रलिस के लिये:

[डाकघर अधिनियम, 1898](#), [लोक व्यवस्था](#), [आपातकाल](#), [लोक सुरक्षा](#), [भू-राजस्व](#), [भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता](#), [नजिता का अधिकार](#)।

मेन्स के लिये:

डाकघर अधिनियम, 2023 का महत्त्व और इसकी कमियाँ।

डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act 2023) को [संसद](#) की मंजूरी विभिन्न लाभ प्रदान करेगी, लेकिन यह डाकघर अधिकारियों को दी गई अनियंत्रित अवरोधन शक्तियों (interception powers) के संबंध में चिंताएँ भी उत्पन्न करती है। नहिति मुद्दों में 'आपातकाल' (जिस पर विचार नहीं किया गया है) एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति, मनमाने ढंग से इसके उपयोग के जोखिम और अधिकारियों द्वारा अवरोधन शक्तियों के संभावित दुरुपयोग जैसे विषय शामिल हैं।

डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य बातें क्या हैं?

डाक सेवा महानिदेशक (Director General of Postal Services):

- हाल ही में पारित अधिनियम डाक सेवा महानिदेशक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश के लिये आवश्यक गतिविधियों से संबंधित नियम बनाने के साथ-साथ इन सेवाओं के लिये शुल्क तय करने का अधिकार देता है।
 - यह उल्लेखनीय है क्योंकि यह पारंपरिक मेल सेवाओं सहित डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिये निर्धारित शुल्क को संशोधित करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

शपिमेंट का अवरोधन:

- अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित विषयों के हित में किसी भी अधिकारी को डाकघर द्वारा संचरण के दौरान किसी भी वस्तु को अवरुद्ध करने, उसे खोलने या नरिद्ध करने का अधिकार दे सकती है:
 - राज्य की सुरक्षा,
 - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
 - [लोक व्यवस्था](#), [आपातकाल](#) या [लोक सुरक्षा](#)
 - इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के किसी भी उल्लंघन के मामले में।
- नए अधिनियम में एक व्यापक प्रावधान शामिल है जिसका उद्देश्य तस्करी और डाक पैकेजों के माध्यम से मादक पदार्थों एवं प्रतबिधित वस्तुओं के अवैध संचरण को रोकना है।
 - केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से किसी अधिकारी को अधिकार सौंपेगी जो अवरोधन को अंजाम दे सकता है।

आइडेंटिफायर्स और पोस्ट कोड:

- अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में कहा गया है कि "केंद्र सरकार वस्तुओं पर पते, एड्रेस आइडेंटिफायर्स और पोस्टकोड के उपयोग के लिये मानक निर्धारित कर सकती है।"
 - यह प्रावधान किसी परसिर की सटीक पहचान के लिये भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा।
 - डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है, जो छँटाई प्रक्रिया को सरल बना सकती है और मेल एवं पार्सल डिलीवरी की सटीकता को बढ़ा सकती है।

अपराधों और दंडों को हटाना:

- अधिनियम में डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी या वनाश के लिये दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है, जैसा

वर्ष 1898 के मूल अधिनियम में रहा था।

■ धारा 7 के तहत जुर्माना:

- प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदत्त सेवा का लाभ उठाता है, ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) में नरिदष्ट शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या इसकी उपेक्षा करता है तो ऐसी राशा इस तरह वसूली योग्य होगी जैसे कयिह उस पर देय [भु-राजसव](#) का बकाया हो।

■ केंद्र की अनन्यता की समाप्ति:

- वर्तमान अधिनियम ने वर्ष 1898 के अधिनियम की धारा 4 को नरिसति कर दिया है जो केंद्र को सभी पत्रों को डाक द्वारा प्रेषण पर अनन्य वशिषाधिकार प्रदान करती थी।
 - कूरयिर सेवाएँ अपने कूरयिर को 'लेटर्स' के बजाय 'डॉक्यूमेंट' और 'पार्सल' कहकर वर्ष 1898 के अधिनियम को दरकनार करती रही हैं।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (Indian Post Office Act 1898)

- यह भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1898 को लागू किया गया था।
- यह केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त डाक सेवाओं के लिये वनियमन प्रदान करता था।
- यह केंद्र सरकार को पत्र प्रेषण पर अनन्य वशिषाधिकार प्रदान करता था और पत्र प्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता था।

डाकघर अधिनियम 2023 में क्या कमियाँ हैं?

■ डाक सेवाओं का कूरयिर सेवाओं से भिन्न वनियमन:

- वर्तमान में सार्वजनिक और नजी कृषेत्रों द्वारा सदृश डाक सेवाओं के वनियमन के लिये अलग-अलग रूपरेखाएँ हैं।
- नजी कूरयिर सेवाएँ वर्तमान में किसी वशिषिट कानून के तहत वनियमित नहीं हैं। इससे कुछ प्रमुख अंतर पैदा होते हैं।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 1898 के अधिनियम ने 'इंडिया पोस्ट' के माध्यम से प्रसारित वस्तुओं के अवरोधन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की। नजी कूरयिर सेवाओं के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान अधिनियम में भी इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
 - एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर उपभोक्ता संरक्षण ढाँचे के अनुप्रयोग में उत्पन्न होता है।
 - [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019](#) 'इंडिया पोस्ट' की सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह नजी कूरयिर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधिनियम 2023 वर्ष 1898 के अधिनियम को प्रतस्थापित करने की इच्छा रखते हुए भी इन प्रावधानों को बनाये रखता है।

■ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है:

- वधियक में डाक वस्तुओं के अवरोधन के वरिद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नरिदष्ट नहीं किया गया है। इससे [नजिता के अधिकार और वाक एवं अभवियकता सिवातंत्र्य के अधिकार](#) का उल्लंघन हो सकता है।
 - दूरसंचार के अवरोधन के मामले में [पीपुलस युनियन फॉर सविलि लबिरीटीज \(PUCL\) बनाम भारत संघ मामले \(1996\)](#) में [सर्वोच्च नयायालय](#) ने माना कि अवरोधन की शक्ति को वनियमित करने के लिये एक उचित एवं सम्यक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिये।
 - अन्यथा [अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) (वाक एवं अभवियकता सिवातंत्र्य) और [अनुच्छेद 21](#) (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में नजिता का अधिकार) के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं होगा।

■ 'आपातकाल' का आधार उचित प्रतर्बिधों से परे है:

- वधिआयोग (1968) ने 1898 के अधिनियम का परीक्षण करते समय पाया था कि 'आपातकाल' (emergency) शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इस प्रकार यह अवरोधन के लिये एक अत्यंत व्यापक आधार प्रदान करता है। इसे वर्तमान अधिनियम में भी बरकरार रखा गया है।
 - इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक आपातकाल अवरोधन के लिये संवैधानिक रूप से स्वीकार्य आधार नहीं हो सकता है, यदि यह राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संवधान में नरिदष्ट किसी अन्य आधार को प्रभावित नहीं करता हो।

■ सेवाओं में चूक के लिये दायित्व से छूट:

- अधिनियम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के वपिरीत है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य वाणजियक सेवा है।
- रेल दावा अधिकरण अधिनियम 1987 (Railway Claims Tribunal Act 1987) भारतीय रेलवे के वरिद्ध सेवाओं में खामियों की शकियतों के नपिटान के लिये अधिकरणों की स्थापना करता है।
 - इनमें माल की हानि, कृषति या गैर-डिलीवरी और करिए या माल की वापसी जैसी शकियतें शामिल हैं।

■ सभी अपराधों और दंडों को हटाना:

- वर्ष 1898 के अधिनियम के तहत, डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलना दो वर्ष तक की क़ैद, जुर्माना या दोनों से दंडनीय था। डाक अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी मेल बैग खोलने के लिये दंडित किया जाता था।
 - इसके वपिरीत, वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत ऐसे कृत्यों के वरिद्ध कोई दंड नहीं होगा। इससे व्यक्तियों की नजिता के अधिकार पर प्रतकिल प्रभाव पड़ सकता है।
 - डाक सेवाओं से संबंधित वशिषिट उल्लंघन [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) जैसे अन्य कानूनों के दायरे में भी शामिल नहीं हैं।

■ कुछ मामलों में परिणामों पर स्पष्टता का अभाव:

- अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी 'इंडिया पोस्ट' द्वारा प्रदत्त सेवा के संबंध में किसी दायित्व का भागी नहीं होगा।
- यह छूट वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ अधिकारी ने धोखाधड़ी से काम किया हो या जानबूझकर सेवा की हानि, देरी या गलत डिलीवरी की हो।

- हालाँकि, अधिनियम यह नरिदष्टि नहीं करता है कयिदकोई अधिकारी ऐसा कृत्य करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी।
- **जन वशिवास अधिनियम, 2023** के तहत संशोधन से पहले वर्ष 1898 के तहत इन अपराधों के लयि दो वर्ष तक की क़ैद, जुरमाना या दोनों की सज़ा का प्रावधान था।

आगे की राह

■ सुदृढ़ प्रकरयात्तमक सुरक्षा उपायों को शामिल करना:

- इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रेषति वस्तुओं के अवरोधन के लयि स्पष्ट और व्यापक प्रकरयात्तमक सुरक्षा उपाय लागू करें।
- इसमें वाक् एवं अभवियकृती की स्वतंत्रता और व्यकृतयिों की नजिता के अधिकार की रक्षा के लयि नरिीक्षण तंत्र, न्यायकि वारंट और संवैधानकि सदिधांतों का पालन शामिल होना चाहयि।
- **न्यायमूरति (सेवानवित्त) के.एस पुट्टासवामी बनाम भारत संघ मामले (2017)** में संचार के अधिकार (right to communication) को नजिता के अधिकार का एक अंग माना गया है और इस प्रकार इसे संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षति कयिा गया है।

■ अवरोधन के लयि आधार को परभाषति करना:

- अवरोधन के आधारों को परषिकृत और स्पष्ट रूप से परभाषति करें, वशिष रूप से 'आपातकाल' शब्द को, ताकि सुनश्चिति हो कयिह संवधान के तहत युक्तयुकृत नरिबंधों के साथ संरेखति हो।
- संभावति दुरुपयोग को रोकने और व्यकृतगित अधिकारों को बनाए रखने के लयि आपातकालीन शक्तयिों के प्रयोग को सीमति करें।
- **ज़िला रजसिटरार एवं कलेक्टर, हैदराबाद बनाम केनरा बैंक मामले (2005)** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कगिराहक द्वारा बैंक के संरक्षण में सौपे गए गोपनीय दस्तावेजों या सूचना के परणामस्वरूप नजिता के अधिकार का लोप नहीं हो जाता।
- इसलयि, यदकि कुछ व्यकृतगित वस्तुओं को पत्राचार के लयि डाकघर को सौपा जाता है तो इसमें व्यकृतके नजिता के अधिकार का लोप नहीं हो जाता।
- न्यायालय ने कई नरिणयों में यह भी कहा है कनजिता का अधिकार तलाशी और जबती से पहले कारणों की लखति रकिरडगि की आवश्यकता को लागू करता है।

■ संतुलति दायतिव ढाँचा:

- डाकघर की स्वतंत्रता और दक्षता को खतरे में डाले बना दायतिव के लयि स्पष्ट नियम नरिधारति कर उसकी जवाबदेही सुनश्चिति करें।
- संभावति दुरुपयोग के बारे में चतिाओं का समाधान करें और हतिों के टकराव को, वशिष रूप से वभिनिन सेवा शुल्क नरिधारति करने के संबंध में, रोकें।
- सक्रम प्राधिकारी को अवरोधन शक्तयिों के कसिी भी मनमाने दुरुपयोग के लयि जवाबदेह ठहराया जाना चाहयि, जहाँ उनके बचाव के लयि 'गुड फेथ' खंड का प्रयोग नहीं हो।
- इन वधिानों के तहत नजिता के अधिकार के उल्लंघन के मामले में, राहत (मुआवजा सहति) केवल संवैधानकि अदालतों से मांगी जा सकती है।

■ अनधकृत अनावरण के मुद्दे को संबोधति करना:

- डाक अधिकारयिों द्वारा डाक वस्तुओं के अनधकृत अनावरण को संबोधति करते हुए, अधिनियम के भीतर वशिषिट अपराधों और दंडों को पुनः लागू करें।
- उपभोक्ताओं के नजिता के अधिकार की सुरक्षा के लयि एक कानूनी ढाँचा स्थापति करें जो व्यकृतयिों को कदाचार, धोखाधड़ी, चोरी और अन्य अपराधों के लयि ज़मिमेदार ठहराए।
- **नागरकि और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 1966)**, जसिमें भारत एक पक्षकार है, का अनुच्छेद 17 कहता है क"कसिी को भी उसकी नजिता, परिवार, घर और पत्र-व्यवहार में मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के अधीन नहीं कयिा जाएगा और न ही उसके सम्मान एवं प्रतषिठा पर गैर-कानूनी हमले कयि जाएंगे।"

नषिकरष:

जबकि वधिायी संशोधन समसामयकि चुनौतयिों से नपिटने के लयि महत्त्वपूर्ण हैं, सुरक्षा अनविर्यताओं और व्यकृतगित अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहयि। उभरते कानूनी परदृश्य में यह सुनश्चिति करने के लयि सावधानीपूर्वक वचिार करने की आवश्यकता है कअवरोधन प्रावधान संवैधानकि सदिधांतों, अंतर्राष्ट्रीय दायतिवों और व्यकृतगित गोपनीयता की सुरक्षा की अनविर्यता के अनुरूप हों।

भवषिय में संवैधानकि चुनौतयिों को रोकने के लयि स्पष्ट प्रकरयात्तमक सुरक्षा उपायों, जवाबदेही उपायों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन सहति वभिनिन अग्रसकरयि कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

अभ्यास प्रश्न: अवरोधन प्रावधानों में प्रकरयात्तमक सुरक्षा उपायों और जवाबदेही उपायों की अनुपस्थतिपर वचिार करते हुए व्यकृतगित नजिता/गोपनीयता के लयि डाकघर अधिनियम, 2023 के नहितार्थों का परीक्षण कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

प्रश्न. 'नजिता का अधिकार' भारत के संविधान के कसल अनुच्छेद के तहत संरक्षत है?

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/post-office-act,-2023-replacing-colonial-legislation>

